

प्रेषक,

संख्या: 66-दो(8) / XXXVI(2) / 2017

आलोक कुमार वर्मा,  
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग - 2

देहसादून : दिनांक : ०४ जनवरी, 2018

विषय: मा० उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल में स्थित जनसामान्य हेतु शौचालयों में सेन्सर युक्त यूरीनल लगाने के कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5040/U.H.C./Admn.B/IX-a/2017, दिनांक 15.11.2017 के संदर्भ मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल में स्थित जनसामान्य हेतु शौचालयों में सेन्सर युक्त यूरीनल लगाने के कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार आगणन एवं टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित धनराशि रु० 5,57,000.00 (रुपये पाँच लाख सतावन हजार मात्र) के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए मा० उच्च न्यायालय के (लेखाशीर्षक '2014-00-102-03-25-लघु निर्माण') निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
- (2) व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (3) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी (जिस रस्तर से आगणन स्वीकृत की गई है) की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
- (4) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18.3.2014 एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV.219(2006), दिनांक: 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (5) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
- (6) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय।
- (7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- (8) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय।
- (9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- (10) आगणन गठिन करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, 2017 बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तदविषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किय जाय। कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों को पूर्णतः पालन किया जाय तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो इस हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- (11) स्वीकृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके न्यूनतम निविदा के सापेक्ष हुई बचत तथा कार्य की जाने वाली सामग्री के लिए स्वीकृत दरों के सापेक्ष हुई बचत की सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से रवीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

2— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 08भारित/XXVII(5)/2017, दिनांक 28 दिसंबर, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( आलोक कुमार वर्मा )

प्रमुख सचिव।

संख्या: 66-दो(8)/XXXVI(2)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—  
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
4. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
5. एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( महेश चन्द्र कौशिवा )

अपर सचिव।